GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO. *52
TO BE ANSWERED ON 02ND DECEMBER, 2021

STIMULUS PACKAGES TO ASSIST ARTISTS OF ODISHA

***52. SMT. MAMATA MOHANTA:**

Will the Minister of LABOUR AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether Government has identified the number of artists in Odisha who have been unemployed due to COVID-19 pandemic and lockdown;

(b) if so, the details thereof, and if not, the reasons therefor;

(c) whether Government proposes to introduce stimulus packages to assist artists of Odisha who have suffered financial loss due to COVID-19 pandemic and lockdown; and

(d) if so, the details thereof?

ANSWER

MINISTER OF LABOUR AND EMPLOYMENT
(SHRI BHUPENDER YADAV)

(a) to (d): A Statement is laid on the Table of the House.

*

STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO PARTS (a) TO (d) OF RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO. *52 DUE FOR REPLY ON 02-12-2021 REGARDING "STIMULUS PACKAGES TO ASSIST ARTISTS OF ODISHA" BY SMT. MAMATA MOHANTA, M.P.

(a) to (d): Government of Odisha has informed that they do not have information regarding unemployed artist due to Covid-19. However, they have organized many awareness programmes during COVID-19 to involve the artists to participate and earn their livelihood. 1.5 lakh folk artists have been identified and enrolled by the Government of Odisha under Artist Federation Scheme. Government of Odisha is also providing monthly financial assistance @ Rs. 1200/- per month to 35,000 numbers of artists of different categories under "Mukhyamantri Kalakar Sahayata Yojana".

Ministry of Culture, Government of India has also taken a number of steps to extend help to artists during Covid-19 pandemic. Financial assistance to the tune of Rs. 9.27 crore has been extended to artists as remuneration, Dedicated help lines were opened to enable the artists to avail maximum benefits of the financial grant schemes, Folk/ Tribal artists were offered online platforms for paid performance and Old artists getting 'Artist Pension' were allowed the release of pension amount by way of granting exemption from the mandatory condition of submission of annual income certificate. Ministry of Culture has ensured speedy and timely release of the grants under the above said schemes to help the artists who faced financial crisis and lost their means of livelihood during Covid-19.

Further, Ministry of Culture is implementing various schemes viz., Financial assistance under Repertory Grant Scheme, Scheme of Financial Assistance for the Development of Buddhist/ Tibetan Art and Culture, Cultural Function and Production Grant Scheme, Scheme of Scholarship & Fellowship for promotion of Art & Culture, Financial Assistance to Cultural Organizations with National Presence, Scheme of Financial Assistance for the Preservation & Development of Cultural Heritage of Himalayas, Scheme of Pension & Medical Aid to Artists, Financial assistance under Seva Bhoj Yojna and Financial Assistance for Cultural Activities in Performing Arts for Building Grants Including Studio Theatres.

*****

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या- *52
गुरूवार, 2 दिसम्बर, 2021/11 अग्रहायण, 1943 (शक)

ओडिशा में कलाकारों को सहायता प्रदान करने के लिए प्रोत्साहन पैकेज

***52. श्रीमती ममता मोहंताः**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के कारण बेरोजगार हुए ओडिशा के अनेक कलाकारों को चिन्हित कर लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ओडिशा के उन कलाकारों की सहायता के लिए, जिन्हें कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के कारण वित्तीय घाटा उठाना पड़ा है, प्रोत्साहन पैकेज शुरू करने का विचार रखती है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार मंत्री
(श्री भूपेन्द्र यादव)

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

*

“ओडिशा में कलाकारों को सहायता प्रदान करने के लिए प्रोत्साहन पैकेज” के संबंध में श्रीमती ममता मोहंता, सांसद द्वारा पूछे गए राज्य सभा के दिनांक 02-12-2021 के तारांकित प्रश्न संख्या *52 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (घ): ओडिशा सरकार ने सूचित किया है कि उन्हें कोविड -19 के कारण बेरोजगार कलाकारों के संबंध में जानकारी नहीं है। तथापि, उन्होंने कलाकारों को अपनी आजीविका कमाने के लिए कोविड-19 के दौरान कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जिसमें उनको भागीदार बनाया गया। कलाकार महासंघ योजना के तहत ओडिशा सरकार द्वारा 1.5 लाख लोक कलाकारों की पहचान की गई है और उनका नामांकन किया गया है। ओडिशा सरकार "मुख्यमंत्री कलाकार सहायता योजना" के तहत विभिन्न श्रेणियों के 35,000 कलाकारों को 1200 रुपये प्रति माह की मासिक वित्तीय सहायता भी प्रदान कर रही है।

संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार ने भी कोविड -19 महामारी के दौरान कलाकारों को सहायता देने के लिए कई कदम उठाए हैं। कलाकारों को पारिश्रमिक के रूप में 9.27 करोड़ रुपए वित्तीय सहायता के रूप में दिए गए हैं, कलाकारों को वित्तीय अनुदान योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाने में सक्षम बनाने के लिए समर्पित हेल्प लाइन खोली गई, लोक/आदिवासी कलाकारों को भुगतान पर कार्यनिष्पादन के लिए ऑनलाइन मंच की पेशकश की गई और पुराने कलाकारों को वार्षिक आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अनिवार्य शर्त से छूट प्रदान करके 'कलाकार पेंशन' जारी करने की अनुमति दी गई। संस्कृति मंत्रालय ने कोविड -19 के दौरान वित्तीय संकट का सामना करने वाले और अपनी आजीविका के साधन खोने वाले कलाकारों की मदद करने के लिए ऊपर उल्लिखित योजनाओं के तहत अनुदानों को शीघ्र और समय पर जारी करना सुनिश्चित किया है।

इसके अलावा, संस्कृति मंत्रालय कोष अनुदान योजना के तहत वित्तीय सहायता, बौद्ध/तिब्बती कला और संस्कृति के विकास के लिए वित्तीय सहायता की योजना, सांस्कृतिक समारोह और उत्पादन अनुदान योजना, कला एवं संस्कृति के प्रचार के लिए छात्रवृत्ति और अधिछात्रवृति की योजना, राष्ट्रीय उपस्थिति वाले सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता, हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और विकास के लिए वित्तीय सहायता की योजना, कलाकारों को पेंशन और चिकित्सा सहायता की योजना, सेवा भोज योजना के तहत वित्तीय सहायता और स्टूडियो थिएटर सहित निर्माण अनुदान की व्यवस्था करने के लिए प्रदर्शन कलाओं में सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता जैसी विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है।

*****

श्रीमती ममता मोहंता : माननीय उपसभापति महोदय, कोरोना वायरस ने सभी कलाकारों को आर्थिक संकट में डाल दिया है। उनकी रोज़ी-रोटी चली गई है। इस संकट से सभी कलाकार प्रभावित हुए हैं, चाहे वे नृत्य, संगीत, रंगमंच या चित्रकारी के कलाकार हों या हमारे ओडिशा के जात्रा कलाकार, छऊ, झुमुर, पाला गायक या नाटककार हों। Social distancing के नियमों का पालन करते हुए इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करना लगभग असंभव हो गया है। सरकार उन कलाकारों को बचाने हेतु क्या मॉडल अपनायेगी जिससे उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधरे और कला भी बचे?

श्री भूपेन्द्र यादव: सर, यह प्रश्न मूलतः कोविड-19 के दौरान जो लोक कलाकार हैं, उनके विषय में पूछा गया है। सरकार के द्वारा कोविड-19 में सभी वर्गों के अंतर्गत जो श्रम का नुकसान हुआ, उसके लिए अनेक योजनाएं चलाई गई हैं। जो संस्कृति मंत्रालय है, उसके द्वारा लोक कलाकारों के लिए कोविड-19 के दौरान जिस प्रकार का प्रबंध किया गया, उसके अंतर्गत 39 से ज्यादा वर्चुअल कार्यक्रम ओडिशा के अंतर्गत किये गये। उसके अलावा 12 ऑनलाइन प्रोग्राम भी सरकार के द्वारा किये गये। जैसे ओडिशा के अंतर्गत ऑनलाइन ओडिशी नृत्य प्रस्तुति, ऑनलाइन संबलपुरी नृत्य प्रस्तुति, ऑनलाइन संगीत उत्सव, ऑनलाइन शंखवादन नृत्य प्रस्तुति, स्वच्छ भारत, ऑनलाइन संगीत उत्सव, मास्क और चित्र की पेन्टिंग प्रदर्शनी पुरी में, ऑनलाइन आदिलोक रंग, ऑनलाइन नृत्य संगीत समारोह, ऑनलाइन नाट्य उत्सव, फेसबुक पेज पर छऊ कनेक्ट, ऑनलाइन नृत्य उत्सव, ऑनलाइन आदिलोक रंग (द्वितीय चरण), ऑनलाइन नृत्य और संगीत (द्वितीय चरण), ऑनलाइन आदिलोक रंग (तृतीय चरण), महात्मा गांधी की 151वीं जयन्ती स्वर्ण उत्सव आदि वे सारे 39 प्रोग्राम्स मैं सभा पटल पर रख दूंगा, जो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, कोविड-19 के दौरान इनका जो रोज़गार छिन गया था, उसके लिए पूरे तरीके से किये गये हैं।

श्रीमती ममता मोहंता: सर, उन कलाकारों को राहत देने के लिए आर्थिक सहायता देने के अलावा और क्या-क्या कदम उठाये गये हैं?

श्री भूपेन्द्र यादव: महोदय, कलाकारों को आर्थिक सहायता के लिए सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान वित्तीय सहायता के लिए कौशल अनुदान योजना के तहत वित्तीय सहायता, बौद्ध-तिब्बत कला संस्कृति के लिए वित्तीय सहायता, सांस्कृतिक समारोह अनुदान योजना, कला संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए छात्रवृत्ति फैलोशिप योजना, राष्ट्रीय उपस्थिति वाले सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता, हिमालय की सांस्कृतिक सहायता के संरक्षण, कलाकारों की पेंशन और चिकित्सा सहायता योजना, सेवा भोज योजना, स्टूडियो, थियेटर से अनुदान बनाने के लिए प्रदर्शनी और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा किये गये और अन्य सारे कार्य, रोजगार उत्पादन के लिए भारत सरकार के द्वारा कलाकारों के अतिरिक्त अगर कोई अन्य व्यक्ति भी रोजगार के अंतर्गत उसमें प्रभावित रहता था, तो भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के द्वारा रोजगार उत्पादक कार्यक्रम भी किये गये, जिनके अंतर्गत श्रम रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत तीन

योजनाएं – आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, राष्ट्रीय कैरियर सेवा परियोजना, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, प्रधान मंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, इनके अतिरिक्त शहरी आवास मंत्रालय में प्रधान मंत्री स्वनिधि योजना, शहरी क्षेत्र में दीनदयाल अंत्योदय योजना, सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग में प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, वित्त मंत्रालय में प्रधान मंत्री मुद्रा योजना, कौशल विकास में प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना, कौशल विकास उद्यमशीलता में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना और इसके अतिरिक्त भी 13 मंत्रालयों के द्वारा उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं को लागू किया गया। व्यापक रूप से सरकार के द्वारा कोविड-19 के दौरान असंगठित क्षेत्र में जिनके भी रोजगार का क्षरण हुआ, उनके लिए व्यापक योजनाओं को लागू किया गया है।

SHRI PRASANNA ACHARYA: Sir, hon. Minister in his reply to the question has stated that 1.5 lakh folk artists have been identified and enrolled by the Government of Odisha under the Artists Pension Scheme. And, at the same time, he has also replied that financial assistance to the tune of Rs. 9.27 crores has been extended to artists as remuneration.

I would like to know from the hon. Minister whether this amount is enough to meet the requirement of total number of artists enrolled under the Artists Pension Scheme.

Sir, during the COVID-19 period, as all of us know, artists of the country, like other sections of people, underwent several financial hardship. During that time, pension under the National Pension Scheme was not released to entitled artists by the Ministry. So, I would also like to know from the hon. Minister what was the total amount required annually to pay pension to artists and what was the total amount released by the Ministry for this purpose.

श्री भूपेन्द्र यादव: सर, आपने जो उत्तर पढ़ा है, उसका केवल पहला पैराग्राफ पढ़ा है, जिसके अन्तर्गत यह लिखा गया है कि संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार ने कोविड के दौरान कलाकारों को पारिश्रमिक के रूप में 9.27 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है। जो दूसरा पैराग्राफ है, उसमें लिखा है कि इसके अलावा, संस्कृति मंत्रालय कोष अनुदान योजना के तहत वित्तीय सहायता.., जो मैंने पढ़ा है, मेरे पास जो तथ्य संस्कृति मंत्रालय के द्वारा उपलब्ध कराये गये हैं, उसके अन्तर्गत 5,462.69 लाख रुपये का अनुदान दिया गया है। इसको मैं सभा पटल पर रख दूँगा।

SHRI PRASANNA ACHARYA: What was the amount released?

श्री भूपेन्द्र यादव: सर, ...(**व्यवधान**)... नोटिफिकेशन के आधार पर ...(**व्यवधान**)... बाकी जो विषय है, मैंने जो योजनाएँ बतायी हैं, उनके अन्तर्गत आता है।

SHRI G.V.L. NARASIMHA RAO: Thank you, Mr. Deputy Chairman, Sir. My question relates to another section of the workers of the country who have suffered greatly on account of COVID pandemic and lockdown. And, the Government was very kind to ensure that about Rs. 8,000

crores were released to them in COVID-1 and COVID-2. **इसके लिए मैं सबसे पहले माननीय मंत्री जी और माननीय प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ।**

My question is, the assistance that was given to the construction and other workers was given in every State of the country. But, the amount of assistance varied from Rs. 1,000 in some States, to Rs. 5,000 in some other States. Even in some States where there were enough resources available in the pool of the welfare cess, they were given only Rs. 1,000. So, I would like to know from the hon. Minister whether any specific guidelines were given with regard to quantum of assistance; or, it was entirely left to the States. If no, why?

श्री भूपेन्द्र यादव: सर, यह प्रश्न इस मूल प्रश्न से अलग है, लेकिन मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि केन्द्रीय स्तर पर एक बोर्ड की स्थापना की गयी और विभिन्न राज्यों में भी इस बोर्ड की स्थापना हम राज्य सरकारों के माध्यम से ही करते हैं। राज्य सरकारें जिस प्रकार के अनुदान और अनुशंसा करती हैं, वह उनके आधार पर किया जाता है।

DR. AMAR PATNAIK: Sir, as the answer suggests, the Government of Odisha provided monthly financial assistance of Rs. 1,200 per month. I would like to know from the hon. Minister whether the Central Government could consider including these people under the scheme of the Central Government, meant for 'unorganized sector', where Rs. 3,000 is given as pension. In which case, it would supplement the efforts of the Central Government. Also, whether interest-free loan can be given to them to the extent of rupees one lakh for a certain period of time, so that they can at least survive for the time-being and later on once the art form comes back to life, they can repay the loan.

श्री भूपेन्द्र यादव: सर, माननीय सदस्य के प्रश्न के दो भाग हैं। पहला विषय ओडिशा के लोक कलाकारों से जुड़ा हुआ है और ओडिशा के अन्तर्गत जो स्कीम है, वह उसके अन्तर्गत आती है। जहाँ तक केन्द्र सरकार की बात है, मैंने विभिन्न योजनाओं के नाम पढ़े हैं, जो संस्कृति मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती हैं। आपका जो तीसरा विषय unorganized sector के लिए है, भारत सरकार के द्वारा unorganized sector के हमारे कारीगरों का एक पूरा डेटा इकट्ठा किया जा रहा है, जिसको *e-sharam* portal के माध्यम से इकट्ठा किया जा रहा है। मुझे सदन को यह बताते हुए खुशी है कि हमने यह तय किया था कि हम 100 दिनों में 10 करोड़ लोगों का रजिस्ट्रेशन करेंगे, लेकिन 100 दिनों से पहले ही माननीय प्रधान मंत्री जी की प्रेरणा से 10 करोड़ के डेटा को हमने प्राप्त किया है और कुल मिलाकर देश में unorganized sector में 160 किस्म के रोजगारों को हमने उसमें दिया है, लेकिन 400 से ज्यादा किस्म के जो occupations हैं, वे देश के अन्तर्गत हैं। देश की सरकार पूरे तरीके से unorganized sector के जो workers हैं, उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। एक वर्ष के लिए उनकी सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था भी की जा रही है। इसके अतिरिक्त भी, भारत सरकार के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में कोविड-19 के नुकसान के बाद unorganized sector में अनेकों कार्यक्रम भी शुरू किये गये हैं, जैसे Digital India, Make in India, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन, राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास प्राधिकरण, Standup India, Startup India, प्रधान मंत्री आवास

योजना, स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन-शहरी, SVSU, Smart Cities Mission, कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन, प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना हैं, जिनमें कोविड-19 के बाद अकुशल क्षेत्र के रोजगारों को बड़ा अवसर प्रदान करने का काम केन्द्र सरकार द्वारा किया गया है।